जनसत्ता

27 फरवरी, 2019

पाक को सबक

भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान की सीमा में चल रहे जैश-ए-मोहम्मद के शिविरों पर बम बरसा कर उन्हें नष्ट कर दिया। आतंकियों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई इस बात का स्पष्ट और कड़ा संदेश है कि भारत अब और आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश करेगा, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। बारह दिन पहले पुलवामा में जैश के आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला कर चालीस से ज्यादा सैनिकों को मार डाला था। तभी सरकार ने साफ कर दिया था कि वह जल्दी ही ऐसी सख्त और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम देगी जिसे हमलावर संगठन कभी नहीं भूल पाएंगे। सेना के पास पुख्ता खुफिया जानकारी थी कि पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी में जैश के बड़े शिविर चल रहे हैं जिनमें भारत में आत्मघाती हमले कराने के लिए लड़ाकुओं को तैयार किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना की इस कार्रवाई में जैश के बड़े कमांडर और आतंकियों के प्रशिक्षकों सहित बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। इन आतंकी शिविरों का संचालन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार मौलाना यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी कर रहा था। आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ भारत की यह बड़ी और निर्णायक कार्रवाई पाकिस्तान के लिए बड़ा सबक है। भारत के इस सख्त रुख से दुनिया के उन देशों को भी कड़ा संदेश गया है जो आतंकवाद की निंदा तो करते हैं, लेकिन गुपचुप रूप से पाकिस्तान के साथ हैं।

पुलवामा हमले के बाद भारतीय जनमानस बेहद आक्रोश में है। जनता सरकार से उम्मीद कर रही थी कि वह पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए, ताकि अब तक के सारे आतंकी हमलों का हिसाब चुकता हो। सरकार पर इसके लिए भारी दबाव था कि अगर पाकिस्तान को पुलवामा हमले का कोई जवाब नहीं दिया गया तो वह और ऐसे हमले करता रहेगा और जनता में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है और सेना व सुरक्षाबलों का मनोबल भी गिर सकता है। हालांकि तीन साल पहले भी भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में ऐसी ही बड़ी कार्रवाई कर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान को संदेश दिया था कि वह अपने यहां चल रहे आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करे और सीमापार आतंकवाद को बंद करे। लेकिन पाकिस्तान ने तब भी इस कार्रवाई से कोई सबक नहीं लिया और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध जारी रखा। लेकिन अब भारत का धैर्य चुक गया है। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि वह भारत के संयम की अब और परीक्षा नहीं ले पाएगा। अगर उसने आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई तो भारत खुद उसके यहां घुस कर आतंकी ठिकानों को नष्ट करेगा।

पुलवामा हमले की जिम्मेदारी भी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। जैश का मुख्यालय पाकिस्तान में है और इस संगठन का मुखिया मौलाना मसूद अजहर है। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा सहित कई आतंकी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ लंबे समय से आतंकवादी जंग चला रहे हैं और इन संगठनों की कमान पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आइएसआइ और सेना के हाथ में रहती है। सारी दुनिया इस हकीकत को जानती भी है। पिछले दो दशकों में भारत ने जितने आतंकी हमले झेले हैं वे अब तक हमारे शासन तंत्र की कमजोरी समझे जा रहे थे। कंधार विमान अपहरण कांड से लेकर करगिल की लड़ाई, संसद भवन पर हमले, मुंबई हमले, पठानकोठ, उड़ी और नगरोटा में हमले- सबने भारत को हिलाया और देश के धैर्य और संयम की परीक्षा ली। लेकिन अब भारत का संदेश साफ है कि किसी भी आतंकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए वह कोई सीमा तय नहीं करेगा।

पिछले दस दिन में भारत ने रणनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से पाकिस्तान को घेरा है। हाल में पाकिस्तान से तरजीही राष्ट्र का दर्जा छीन लिया गया है। अमेरिका और यूरोपीय महासंघ ने भी उसे चेताया है। भारत अब पूरी दुनिया में अपने राजनयिक चैनलों के जरिए भी पाकिस्तान की करतूतों को सबूतों के साथ रख रहा है। भारतीय नेतृत्व के लिए यह मौका है जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए। वैचारिक मतभेदों को भुलाते हुए देश के राजनीतिक दलों ने भी सरकार के साथ जो एकजुटता दिखाई है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

सरोकार की स्वीकृति

भारत में माहवारी से जुड़े विषय पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री 'पीरियडः एंड ऑफ सेंटेंस' को अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऑस्कर पुरस्कार मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि हमारे देश में आज भी माहवारी को महिलाओं के जीवन का ऐसा हिस्सा माना जाता है, जो एक प्राकृतिक चक्र होने के बावजूद उनके लिए कई तरह की समस्याओं का कारण बनता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की लड़कियों और महिलाओं सहित उनके गांव में पैड मशीन के इर्द-गिर्द बुनी गई छब्बीस मिनट की इस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी में ऑस्कर मिला। इसमें भारत में माहवारी से जुड़ी वर्जनाओं के खिलाफ महिलाओं की लड़ाई और असली जिंदगी के 'पैडमैन' अरुणाचलम मुरुगनाथम के काम को भी दर्शाया गया है। पुरस्कार स्वीकार करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की निर्देशक रायका जेहताबची ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि माहवारी को लेकर बनी कोई फिल्म ऑस्कर जीत सकती है।

रायका जेहताबची की यह बात उन समाजों के संदर्भ में जरूर सही है जहां माहवारी को स्त्रियों की प्राकृतिक बुनावट का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और समाज उसके प्रति पूरी तरह सहज है। लेकिन भारत जैसे देश में यह छिपी बात नहीं है कि समाज में स्त्री के प्रति दृष्टिकोण और उसके व्यक्तित्व को शरीर में समेट कर देखने की मानसिकता ने इस अहम प्राकृतिक चक्र को भी महिलाओं के सामान्य जीवन को बाधित करने वाले कारक के रूप में रूढ़ कर दिया। नतीजतन, जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा जहां स्त्री के लिए जरूरी और सामान्य होना चाहिए, वहां इस चक्र से गुजरने वाली महिलाओं को अनेक जड़ परंपराएं, भेदभाव और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खबरें यहां तक आ चुकी हैं कि माहवारी की वजह से किसी महिला को इस तरह के हालात में रहना पड़ा कि उसकी जान चली गई। आज भी हमारे देश में समाज के ज्यादातर हिस्से में इससे जुड़ी वर्जनाओं और महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार अपने आप में एक सवाल है कि इस मसले पर हमारी सोच कितनी आधुनिक और विकसित हो सकी है!

ऐसे में इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर जैसे विश्व स्तर के पुरस्कार के लिए चुना जाना अपने आप में एक बेहद अहम उपलब्धि है। पितृ-सत्तात्मक मूल्यों से संचालित समाज में लैंगिक पूर्वाग्रहों का हासिल कई बार स्त्रियों के लिए बेहद त्रासद होता है। अगर यह किसी एक घटना की शक्ल में होता है तब भी किसी सभ्य समाज को उसकी वजहों की पहचान और उससे निजात पाने के इंतजाम करने चाहिए। लेकिन इन आग्रहों की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं को बहुस्तरीय मुश्किलों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो यह स्थिति समाज के चेतनागत विकास पर सवाल उठाती है। ऐसे में कई तरह की सामाजिक जड़ताओं के बीच माहवारी से गुजरने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा पैड बनाने से लेकर लोगों को इसके प्रति सहज करने की गतिविधियों को फिल्म का विषय बनाने और उसके ऑस्कर जीतने को वैश्विक स्तर पर भारत में इस मसले पर कुछ लोगों के सरोकारों की स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है।

कल्पमेधा

सच तो यह है कि हिंसा उन लोगों पर पलटवार करती है जो हिंसा फैलाते हैं।
-आर्थर कानन डायल

शहरीकरण और चुनौतियां

ज्योति सिडाना

नवउदारवाद और वैश्वीकरण के बाद अब गांव केवल खाद्य, श्रम एवं कच्चे उत्पादों के आपूर्तिकर्ता बन कर रह गए हैं। शहर आधुनिकीकरण व उपभोक्तावादी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश गांव इन शहरों से अपने अस्तित्व के लिए जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत शहरीकरण, औद्योगीकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं पलायन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और नई पीढ़ी ने गांवों से शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है।

दावोस में पिछले महीने हुए विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में यह बात उभर कर आई कि शहरों के विकास को ही भारत के विकास की धुरी माना जा रहा है। आजकल शहरीकरण विकास का प्रतीक इसलिए बन गया है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए वहां ज्यादा लोग रोजगार में लगे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में वे अधिक धन कमाते हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। आंकड़ों के अनुसार सन 2001 तक भारत की आबादी का 27.81 फीसद हिस्सा शहरों में रहता था। सन 2011 तक यह 31.16 और 2018 में 33.6 फीसद हो गया। जबकि 2001 की जनगणना में शहर-कस्बों की कुल संख्या 5161 थी, जो 2011 में बढ़ कर 7936 हो गई। आज तीन भारतीयों में से एक भारतीय शहरों और कस्बों में रहने लगा है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है और 2050 तक भारत की आधी आबादी महाशहरों और शहरों में रहने लगेगी। तब तक विश्व की आबादी का सत्तर फीसद हिस्सा शहरों में रह रहा होगा।

वैश्वीकरण के उपरांत शहरी विकास की अवधारणा समावेशी विकास की एक आवश्यक शर्त बन कर उभरी है। शहरी विकास की इस प्रक्रिया ने गांवों के सामने अस्तित्व के संकट उत्पन्न किए हैं। शहरों के अनियोजित विकास, महानगरों का असुरक्षामूलक परिवेश एवं शहरी संस्कृति में उत्पन्न होते संबंधमूलक तनाव शहरी विकास की पुनर्समीक्षा के लिए हमें बाध्य करते हैं। आप चाहे विकास की कितनी भी चर्चा कर लें, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने में गांवों की तुलना में शहरों की भूमिका अधिक है, ऐसे में क्या विकास और प्रदूषण का एक दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध है? शहरों में तनाव भी तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि यहां पर संपत्ति संबंधी और आर्थिक असमानता अधिक पाई जाती है, या कहें कि प्रत्येक प्रकार की असमानता का केंद्र शहर ही हैं। उदाहरण के लिए, भारत की शीर्ष दस फीसद आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 77.4 फीसद हिस्सा है। इनमें से सिर्फ एक फीसद आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 51.53 फीसद हिस्सा है। भारत की साठ फीसद आबादी के पास देश की सिर्फ 4.8 फीसद संपत्ति है। देश के शीर्ष नौ अमीरों की संपत्ति पचास फीसद गरीब आबादी की संपत्ति के बराबर है। यह विकास का कैसा पैमाना है जहां यह कहा जा सके कि जब शहर होंगे तभी देश तीव्र विकास की ओर अग्रसर होगा।

इसको आधार बना कर कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना जरूरी हो जाता है। पहला सवाल तो यह कि शहर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं क्योंकि हरित क्षेत्र को शहर के विकास के लिए समाप्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने अनेक शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है, विशेषतः समुद्र किनारे बसे शहर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं हैं। दूसरा सवाल यह कि शहरों में बड़ी संख्या में कच्ची बस्तियां बन गई हैं। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबंधित उच्च एवं मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु खुद न केवल गरीबी के शिकार हैं अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास ने शहरों में अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूहों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। प्रत्येक शहर में बेतरतीब यातायात एक गंभीर समस्या बन गया है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। शहर में निवास करने वाले समृद्ध लोग अपनी शक्ति और संपन्नता के प्रदर्शन के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि लगभग प्रत्येक शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षा संस्थानों के निजीकरण एवं कारपोरेटीकरण ने शहरों में असमानताओं को जन्म दिया है। सड़कों का निर्माण शहरी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया है।

शहरों की सड़कों पर गड्ढे, सीवर प्रणाली का अभाव एवं बारिश में गंतव्य पर पहुंचने का कष्ट, बिजली, पानी एवं संचार सुविधाओं का अस्त-व्यस्त व असमान रूप शहरी जीवन को इतना अधिक समस्यामूलक बना देता है कि अनेक शहरों

में महज जाने की कल्पनाभर तनाव उत्पन्न कर देती है। वास्तव में शहर असमानता, संघर्ष, ईर्ष्या एवं तनाव के केंद्र बन गए हैं। अपराध की दृष्टि से भी शहर तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि कंक्रीट के जंगल में लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। या कहें कि भावनाशून्यता, संवादहीनता और व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति शहरी जनसंख्या के जीवन का हिस्सा बन गई है।

सभ्यता का जो स्वरूप यूरोप ने पेश किया उसमें गांव और शहर का एक साथ रहना संभव ही नहीं है। गांधीजी ने इस सभ्यता को अधर्म की संज्ञा देते हुए कहा था कि यह सभ्यता शरीर सुख को ही जीवन का लक्ष्य समझती है, जिसे आज हम उपभोक्तावादी सभ्यता और संस्कृति के रूप में जानते हैं। जहां परंपरागत भारतीय गांव संस्कृति की पूर्णता को प्रदर्शित करते थे, वहीं शहर प्रशासनिक इकाई की भूमिका का निर्वाह करते थे। नवउदारवाद और वैश्वीकरण के बाद अब गांव केवल खाद्य, श्रम एवं कच्चे उत्पादों के आपूर्तिकर्ता बन कर रह गए हैं। शहर आधुनिकीकरण व उपभोक्तावादी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश गांव इन शहरों से अपने अस्तित्व के लिए जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत एक तरफ शहरीकरण, औद्योगीकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं पलायन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और नई पीढ़ी ने गांवों से शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर यह भी एक तथ्य बन कर उभरा है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय, महानगरों में लंबे समय से रह रहे परिवार पर्यावरण-प्रदूषण और पारिस्थितिकीय असंतुलन जैसी समस्याओं से परेशान होकर गांवों के प्रति अपने लगाव को अभिव्यक्त करने के लिए महंगे फार्महाउसों का निर्माण कर रहे हैं। यह भी सत्य है कि गांव से जुड़ी लोक संस्कृति, लोककला, लोकनृत्य, लोकसंगीत, वेश-भूषा एवं खान-पान आदि का प्रयोग अब शहरों में स्थापित होटल उद्योग अपने व्यावसायिक लाभों में वृद्धि करने के लिए उपयोग में ला रहे हैं।

इस संदर्भ में मैनुअल कैसेल द्वारा प्रस्तुत 'नेटवर्क सोसायटी' की अवधारणा की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। इसे 'स्मार्ट सिटी' के रूप में भारत में समझे जाने की आवश्यकता है। शहर की भौगोलिक सीमा का जितना अधिक विस्तार होगा, हमें नए नेटवर्क बनाने की उतनी ज्यादा आवश्यकता होगी, ताकि सुविधाओं एवं सेवाओं का तार्किक एवं समय सीमाओं के अंतर्गत वितरण हो सके। कंप्यूटर जनित संचार आने वाले समय में हर शहर की जरूरत बनेगा। परंतु इसके साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है कि निर्धनता, साक्षरता की निम्न दर, असमानता एवं कंप्यूटर के उपयोग को न जानने वाले अथवा कम जानने वाले लोगों के लिए शहर रहने की दृष्टि से समस्यामूलक हो जाएंगे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कहीं स्मार्ट शहरों में निम्न वर्ग या हाशिये की आबादी का कोई स्थान होगा या केवल वही लोग निवास करेंगे जिन्हें कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशेषज्ञता हासिल है? क्या ये शहर बहुमंजिली इमारतों के ऐसे जंगल होंगे जिनमें व्यक्तिवादिता का मूल्य निवास करेगा और मानवीय संबंधों के स्थान पर मोबाइल और कंप्यूटर वैचारिक आदान-प्रदान का स्थान ले लेगा। यह उपयुक्त समय है जब भारत में विकास की दिशा पर सार्वजनिक बहस होनी चाहिए।

दूरी की तकनीक

बृजमोहन आचार्य

दुनिया मेरे आगे

मैं जिस घर में रहता हूं, उसकी ऊपरी मंजिल पर कुछ विद्यार्थी कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। उनके अभिभावकों ने उन्हें पशु चिकित्सक की पढ़ाई करने के लिए भेजा हुआ है और वे हर माह उनके बैंक खातों में कुछ राशि जमा करा देते हैं, ताकि उनके बच्चों को दूसरे शहर में रहते हुए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और मोबाइल पर अंगुलियां चलाने में ज्यादा लगा रहता है। एक रात मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि कानों में आवाजें आने लगीं कि 'इसे गोली मार दे, इसे छोड़ना मत और बंदूक को सही तरीके से पकड़ ले।' ये आवाजें सुन कर एक बार तो मैं घबरा गया कि इतनी देर रात किसकी और कहां से आवाजें आ रही हैं और कौन किसे गोली मार रहा है! लेकिन जब उठ कर खिड़की के पास जाकर गौर से आवाजें सुनीं तो पता चला कि ऊपरी मंजिल पर रह रहे विद्यार्थी मोबाइल पर गेम खेल रहे थे।

पहले मोबाइल पर बिना आवाज किए लोग खेलते थे। लेकिन अब एक नया खेल चल रहा है, जिसे 'पबजी खेल' कहते है। इसमें जिंदगी को शांतिपूर्वक जीने के अलावा बंदूक से किसी अन्य पर हमला कर खेल को जीतना होता है। जबकि सबको याद है कि कुछ समय पहले 'ब्लू वेल' खेल में कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई थी। इसमें बच्चे अपनी जिंदगी को समाप्त करने तक के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाते थे। हालांकि 'पबजी खेल' में यह नौबत नहीं आती है, लेकिन देर रात तक जगने और बंदूकों से हमला करने जैसे अवगुण जरूर सीख जाते हैं। जब इन बच्चों से इस खेल के बारे में अन्य जानकारी चाही तो सभी ने कहा कि इसे खेलने में मजा आता है। अब उन्हें कौन समझाए कि उनके अभिभावकों ने उन्हें अपनों से दूर भेज कर कुछ बनने और देश या समाज की सेवा करने के लिए भेजा हुआ है। इस खेल में ये बच्चे इतने डूब गए हैं कि कक्षा में भी किताबों को एक किनारे रख कर आपस में टीम बना कर पबजी खेलने लगते है।

यह सही है कि मोबाइल के आविष्कार ने कई दूरियों को नजदीकी में बदला है लेकिन लोग अपने जगे होने के दौरान अधिकांश समय मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। स्थिति यह है कि मोबाइल की वजह से युवा वर्ग ने हाथ में घड़ी तक बांधना छोड़ दिया है। जबकि पहले घड़ी को अहम हिस्सा माना जाता था। जो अभिभावक खुद दुख और तकलीफ भरा जीवन जी कर अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, मां परीक्षा के मौसम में रात-रात भर जाग कर बच्चे को परीक्षा की तैयारी कराती है, उसका लाडला पबजी या अन्य वीडियो गेम में अपना भविष्य झोंकने में लगा हुआ है। उसे इससे कोई सरोकार नहीं है कि अभिभावक उसके कुछ बनने के लिए पैसों की कैसे व्यवस्था करते हैं।

बच्चों की यह हालत देख कर मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अपनी ही जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बच्चे मोबाइल में इतने क्यों डूब रहे हैं। हालांकि दूर रह रहे लोगों के लिए मोबाइल आवश्यक हो गया है। लेकिन क्या यह जरूरत भर तक सीमित है? आज हालात ये हो गए हैं कि हर घर में तीन से चार मोबाइल मिल जाएंगे। इनमें से ज्यादातर युवक हैं, जिन्हें अपने विद्यार्थी जीवन में मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। मगर समाज में अपना स्टेटस दिखाने के लिए लोग महंगा स्मार्ट फोन खरीदने की जुगत में रहते है।

दरअसल, मोबाइल के लाभ और नुकसान दोनों हैं। इस उपकरण ने कई बड़े खुलासे करने में भी अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में यह उपकरण नुकसान ही करता है। अभिभावकों के लिए यह सुविधा जरूर हो गई है कि जब मन किया तब दूर बैठे अपने बच्चों से मोबाइल पर बात कर लेते हैं। स्थिति यह हो गई है कि अगर किसी वजह से बच्चा फोन रिसीव नहीं करता है या फोन बंद होता है तो अभिभावक को चिंता सताने लगती है और वे तुरंत किसी अन्य को फोन करके उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या यह नहीं हो सकता कि अभिभावक स्कूल या कॉलेज के बेसिक फोन पर ही बच्चे से बात कर उसकी स्थिति को जान सकें? अभिभावकों को अगर बच्चों को मोबाइल देना भी है तो एक सामान्य मोबाइल फोन उपलब्ध करा देना चाहिए, ताकि सिर्फ बातचीत हो सके। आज हर कॉलेज या स्कूल के विद्यार्थी के पास महंगा स्मार्टफोन उपलब्ध है। सोचने की जरूरत है कि ये फोन बच्चों के जीवन में गुणात्मक बेहतरी लाने में कितने मददगार साबित हो रहे हैं।

आतंक के खिलाफ

पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हवाई हमला कर उसके अनेक आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया है। कहा जा रहा है कि वायुसेना की इस बड़ी कार्रवाई में करीब 300 आतंकवादी मारे गए हैं और इनमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का बहनोई यूसुफ अजहर भी है जो यह शिविर चला रहा था। भारतीय वायुसेना को इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने में 12 मिराज फाइटर जेट का सहारा लेना पड़ा जिन्होंने करीब 1000 किलो बम भी बरसाए।

भारत ने इस हमले के जरिए जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आतंकी शिविरों पर हमले के बाद भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद भारत में फिर फिदायीन आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए हमला करना जरूरी हो गया था। नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार भारतीय वायुसेना के हमले में बालाकोट, चकोठी और मुजफ्फराबाद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। जैश-ए-मोहम्मद के कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इन शिविरों में लश्कर और हिज्बुल के भी शिविर शामिल थे। विजय गोखले के मुताबिक बालाकोट का शिविर जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा शिविर था। ऑपरेशन का निशाना खासतौर से आतंकी अड्डों को बनाया गया था ताकि नागरिकों को नुकसान न हो। इस हमले पर पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया हुई है और अब वह बदला लेने की धमकी दे रहा है।

यहां गौरतलब है कि भारत का यह ऑपरेशन पूरी तरह आतंकियों के खिलाफ था, न कि पाकिस्तान और उसकी अवाम के विरुद्ध कोई युद्धक कार्रवाई। उसे इस हमले के बाद अत्ममंथन करते हुए अपनी आतंकवाद-पोषक नीतियों को तिलांजलि देकर मुल्क के बाकी हिस्सों में मौजूद इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों और उनके आकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसे नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद को खाद-पानी देने का रास्ता एक दिन उसे आत्मघात की ओर ही ले जाएगा।

● *अमन सिंह, प्रेमनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

गरीबों की चिंता

देश में गरीबी की हालत को देखते हुए जरूरी नहीं कि राज्य सरकारें गरीबों के कल्याण की हर केंद्रीय योजना को सही तरह अपनाएं, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि गरीब तबका खुद भी अपने हितों के लिए और अधिक जागरूक हो। निर्धन वर्ग के लोगों को अपनी सेहत और बेहतर भविष्य के लिए किस तरह और कितने सजग होने की जरूरत है, इसे बयान कर रही हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम की वे घटनाएं जिनमें जहरीली शराब पीने के कारण सैकड़ों लोग मर गए। ऐसी घटनाओं की खबरें देश के किसी न किसी हिस्से से अक्सर आती रहती हैं। ये बताती हैं कि एक तो हमारी समूची व्यवस्था में गरीबों के हितों की रक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव है और दूसरे, इस तबके के लोग खुद भी अपने भले-बुरे की चिंता नहीं कर रहे हैं। समय की मांग है कि राज्य सरकारें अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाएं।

● *हेमंत कुमार, ग्राम/पोस्ट-गोराडीह, भागलपुर*

हिंदी का गौरव

जहां भारत में हिंदी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की अदालतों में वह तीसरी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनी वैश्विक पहचान बना रही है। अबू धाबी ही नहीं, अमेरिका के कई विभागों ने अपने ट्विटर हैंडल हिंदी में रखे और अनेक विभागों को हिंदी के अनुसार तैयार किया है। अमेरिकी विदेश विभाग का आधिकारिक पेज हिंदी में है जो उसकी अंतरराष्ट्रीय नीति को हिंदी में पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंदी में ट्विटर हैंडल बनाकर उसे विश्व मंच पर सम्मानित किया है। वर्ष 2018 में हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में न्यूज वेबसाइट शुरू की थी। इसके साथ ही हिंदी पूरे एशिया में एकमात्र ऐसी भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा न होने के बावजूद उसकी तरफ से लांच होने वाली वेबसाइट की भाषा बनी।

भारत पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को कार्यकारी भाषा बनाए जाने की मांग कर रहा है और इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में क्षेत्रीयता के नाम पर कभी तमिलनाडु तो कभी बंगलुरु में हिंदी को प्रतिबंधित करने की मांग की जाती है। अबू धाबी का फैसला हमारे यहां भी एक उदाहरण बन सकता है अगर हम उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी को कामकाज की मुख्य भाषा बनाएं जहां आज भी अंग्रेजी ही मुख्य भाषा है। इन दिनों सरकार सभी विभागों के हिंदी में काम करने पर बल दे रही है तो फिर अदालतें इससे बच क्यों रही हैं? यह समझ से परे है। विश्व स्तर पर हिंदी संबंधी गतिविधियों के समन्वय के कारण ही मारीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हुई जिसने 11 फरवरी 2008 को आधिकारिक रूप से काम करना शुरू भी कर दिया। भारत के माथे की बिंदी हिंदी विदेश में भी सम्मानजनक दर्जा हासिल कर रही है पर भारत में हिंदी में बात करना अब भी पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है और उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग हिंदी को अब भी दोयम दर्जे की भाषा मानते हैं। अबू धाबी का फैसला ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है।

● *देवानंद राय, दिल्ली*

शराब से तौबा

नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के सर्वे के अनुसार बिहार में आम लोगों ने शराब से तौबा करने के मामले में गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। आम बिहारवासी धीरे-धीरे शराब के दुष्परिणामों से सबक लेकर उससे कन्नी काट रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम में जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाए या न लगाए, लेकिन आम आदमी को खुद इस बला से तौबा करके पिंड छुड़ाना चाहिए। आज देश में जो भी सड़क हादसे या अपराध हो रहे हैं उनमें शराब का दोष 60 से 70 प्रतिशत है। आम बिहारवासियों का यह सकारात्मक संदेश अन्य प्रदेश सरकारों और लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए।

● *हेमा हरि उपाध्याय, जावरा रोड, उज्जैन*